

सम्पादकीय

बहुआयामी गरीबी की चुनौती

इन दिनों दशभूमि में सुरक्षा का आधारनयन के दायर में लीया गया है। इस्थिति यह है कि अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री के कल्पणा अन्य योजना लागू की गई और इससे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। यह योजना मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने देश के मुताबिक जनधन, आधार और मोबाइल (जेम) के कारण गरीब व कमज़ोर वर्ग के करोड़ों लोग डिजिटल दुनिया से जु़हर कर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं रहे हैं। देश में करीब 43 करोड़ जनधन खातों, 130 करोड़ आधार कार्ड और 118 करोड़ लोगों के पास मोबाइल उपकरण, होने के कारण पिछले वर्ष 2020 में सरकार के द्वारा घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान से 40 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के लोगों तक उनके खातों में सीधे 65 प्रतिशत और मेघालय में 32. 67 प्रतिशत आवादी गरीब है। इस सूचकांक के तहत केरल में 37.79 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 36. 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 36. 65 प्रतिशत और मेघालय में 32. 67 प्रतिशत आवादी गरीब है। इस सूचकांक के तहत केरल में 0.71 प्रतिशत, गोवा में 3.76 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.89 प्रतिशत और पांजाब में 5.05 प्रतिशत जनसंख्या गरीब पाई गई है। इस रिपोर्ट में बहुआयामी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक देश के छोटे किसान

गरीबी के आकलन के लिए वर्ष 2015–16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के चौथे दोर के संगकों को आपात बनाया गया है। नीति आयोग के मुताबिक बहुआयामी गरीबी सूखाकांक में एनएफएचएस के द्वारा वर्ष 2019–20 में किए गए पांचवें दौर के सर्वे के परिणामों से बड़ा परिवर्तन होगा।

कारण यह है कि एनएफएचएस सरलतापूर्वक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अगस्त 2021 तक 11.37 करोड़ किसानों के बैंक तात्त्वों में डीबीटी की जरिये 1.58 लाख करोड़ रुपए जमा इए जा चुके हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को दूर करने में स्वामित्व योजना को एक नई आर्थिक शक्ति बनाया जा सकता

के बौद्धी राउड के बाद देश में प्रधानमंत्री आवास जल जीवन परिवार, स्वच्छ भारत परिवार, सहम परिवार हर घंटे योजिला, उच्चज्ञ योजना, जनधन योजना, पोषण अभियान समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई है। इनसे सभी राज्यों में गरीबी के स्तर में कमी आने की संभावना है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2014–15 की तुलना में 2019–20 के दौरान रसोई गैंस से वर्धित लोगों की संख्या 58.5 प्रतिशत से घटकर 41.4 प्रतिशत, स्वच्छता से वर्धित आवादी की संख्या 29.8 फीसदी और जिली से वर्धित आवादी का प्रतिशत 12.2 फीसदी से घटकर 3.2 प्रतिशत रह गया है। इसमें कोई दो भूत नहीं है कि कोविड-19 ने भारत में गरीबी और भूख की चुनौती को बढ़ाया है। पिछले दशक में देश में जिस तेजी से गरीबी में कमी आ रही थी, उसे अकल्पनीय कोरोना संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है और देश के अधिक जनसंख्या वाले बड़े प्रदेशों में गरीबी शुरू किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005–06 से वर्तमान तक कार्यक्रम में बुरुआली शामिल होते हुए देश के 3000 गांवों के 1.71 लाख ग्रामीणों को अधिकार पत्र सौंपे हैं। इस योजना के सूत्र मध्यप्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा वर्ष 2008 में उनके राजसव मंत्री रहते तैयार की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार योजना से आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। इसके तहत 2 अक्टूबर 2008 को हरदा के दो गांवों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भूखड़ों के मालिकाना हक के पट्ट ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के माध्यम से दोनों गांवों के किसानों व मजदूरों को सौंपे गए थे। इन दोनों गांवों के किसानों व मजदूरों का जोरदार आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। इस अभियान से दोनों गांवों में अनेक लोगों ने अपनी स्वामित्व की जगीन पर बैंकों से सरलतापूर्वक क्रेंच ले कर छोड़े—कूटी और ग्रामीण उद्योग शुरू किए हैं।

रिपोर्ट के तुलनात्मक पर 2005-06 में भारत में 51 फीसदी लोग गरीबी में थे। यह प्रतिशत 2015-16 में 27.9 फीसदी रह गया और इसमें लगातार कमी आती जा रही थी। कोरोना के एक साल में देश को गरीबी के मामले में देश को कई वर्षों पीछे धकेल दिया और कोरोना ने करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया। अमरीकी शोध संगठन पूरे रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने भारत में बीते साल 2020 में 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दबदबा में धकेल दिया है। रिपोर्ट में प्रतिदिन 2 डॉलर यानी करीब 150 रुपए कमाने वाले को गरीबी की श्रीमती में रखा दिया है। इसमें कोई दो घंट मन नहीं है कि जहां सरकार गरीबी, भूख, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। कौशिंड-19 के बाद इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो पहल ठर आवधि अनुभव कर रहा था उन्हें दुनिया के विभिन्न वैशिक संगठनों ने भी इसकी सराहना की है। यदि कोरोनाकाल में सरकार के ऐसे सफल अभियान नहीं होते तो देश में बहुआयामी गरीबी और बड़ी हुई दिखाई देती। बढ़ा है। जैविक पर्यावरण की खुशियां बढ़ी हैं। ऐसे में देशमें के गांवों में स्वामित्व योजना के तेजी से लापू होने से किसानों की गैर कृषि आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चम्पकीली रिश्ते बनाई जा सकेगी। निरिचत रूप से इस समय देश में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल सेवाएं, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के साथ-साथ उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाने की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। स्वास्थ्य व्यय में वर्षद्वितीय के साथ-साथ गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक और सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दी रही किमियों के दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण के साथ नए रिकल्ट्स रीखाना होंगे। हम उम्मीद करें कि देश में बहुआयामी गरीबी, भूख और कृपोषण खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा धोखित नई जनकल्याण योजनाओं, सामुदायिक रसोइ व्यवस्था तथा पोषण अभियान-2 को पूरी तरह सरकार व सफल बनाया जाएगा। हम उम्मीद करें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 2019-20 के पांचवें दौर के अंतिम परिणामों के आधार पर जब आगामी नव्या बहुआयामी गरीबी सूक्षकां प्रस्तुत होगा, तब उसमें अधिक

—प्रो. सुरेश शर्मा—
वर्तमान में हमारे सभी त्यौहारों, संस्कारों, रीति-रिवाजों का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण हो चुका है। संचार माध्यमों की घुसापैठ तथा भौतिकवादी सोच हमारे सभी रीति-रिवाजों, संस्कारों तथा त्यौहारों में झलक रही है। देखी तथा साधनों के अभाव के बावजूद आम तथा गरीब व्यक्ति भी इन आयोजनों के लिए मजबूर हो चुका है। भौतिकवादी चक्करवाही तथा विचार शून्यता से संस्कृति, रीति-रिवाजों तथा संस्कारों की परिमाणाएँ ही बदल गई हैं। शारीरिक समारोहों में कई प्रकार के रस्मों—रिवाजों, धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों का प्रावधान है जिसमें देवताओं के आहवान के साथ-साथ हल्दी, मेहंदी, उबटन, मामा आगमन, घोड़ी, जयमाला, सात फेरे, हवन, वेदिका पूजन, मांग भरना, आनंद-विनाद एवं छेड़छाड़ के उद्दरश्य से दुल्हन की बहनों की छहलियां द्वारा द्वारा रोकाना या जूते सुहेलीया लेना, बारातियों को गतियां देना, विदाइ तथा वधु प्रवेश आदि रस्मों—रिवाज हमारे शादी समारोह को यार चांद लगाकर विर स्मरणीय बना देते हैं।

विवाह संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह होता है। यह संस्कार युक्त एवं युवती को जहां एक—दूसरे के हाथों में सौंप भविष्य के अनंत सपनों, उमंगों तथा खुशियों से दामन को भर देता है, वहीं पर यह पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी जिद्दमेदारी का एहसास करवाता है। विवाह संस्कार में विभिन्न रस्मों—रिवाजों के पीछे कोई न कोई महत्व एवं गूढ़ रहस्य होता है जिसे शादी के गोप्य सभी युवा—युवतीयों को जाना एवं समझना चाहिए अन्यथा कोई ऐरेज तथा आन्द्र विकल्पों पर भी विवाह किया जा सकता है। आजकल बहुत सा शिक्षित युवा वर्ग शादी की आवश्यकता को न समझते हुए लिव इन लिवशनशिप में भी रह रहा है। भारतीय परिप्रेक्षण में इसे सामाजिक रूप से मान्यता नहीं है। वर्तमान में शादी समारोह में लाखों रुपए की राशि खर्च कर भव्य आयोजन किए जाते हैं। एक से बढ़कर एक शादी आयोजित होती है, लेकिन कोई भी शादी समारोह इतिहास के पन्नों में भव्य आयोजन के रूप में आज तक अपना पंजीकरण नहीं करवा पाया। इसका कारण यह है कि भौतिकवादी की इस भेड़ चाल में काई भी धनवान तथा संपन्न व्यक्ति अपने कामी आयोजनों में किसी प्रकार की नहीं रहने देना चाहता। विवाह संस्कार की महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। व्यूटी सैकून संचालकों के सस्ते से महंगे पैकेजेस हैं। बैंड—बाजे वाले तथा ढोती चाहते हैं कि बाराती शराब के नशे में धूत—मदमत्त होकर सारी रात नाचते रहें तथा पैसे की बरसात होती रहे।

उनकी ओर से लग मुहूर्त का समय निकले तो निकलता रहे। घोड़ी वाले का पैसे बनाने का अपना समय है। पंडित जी की अपनी मजबूरियां हैं। फोटोग्राफर एवं लीडिंगप्रोग्राफर को अपना विजनेस

उत्तर पाटेषा विद्यावस्था च

करना है। दूल्हे की दोस्तों तथा दुल्हन की सहेलियों की अपनी भूमिका है। शादी कार्य छापने से लेकर मिठाई, खाना, टैट, कॉरिंग, लाइट एंड बार, डैकरेशन, व्यूटी सैलून, बड़े-बड़े होटलों में ठहरने के इत्याजम, महंगी से महंगी शाराब, कुल गिलाकर शादी एक संस्कार समारोह न बन कर एक इंवेट मैनेजमेंट बन चुका है। इंवेट मैनेजमेंट में कितने लोगों का इंतजाम, क्या—क्या रिकावायरमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, कॉकटेल, डिनर का मैन्यू तथा बजट महत्वपूर्ण है। केवल बोक पैमेंट पर सब कुछ एकदम तयार गिलता है। आपको सिर्फ कोटे-पेट तथा टाई लगाकर सज-ए-ज कर आयोजन स्थल पर रोबोट की तरह हाथ जोड़ते हुए लोगों का स्वागत करना है। पड़ोसी तथा रिशेदवार मात्र तीन घंटे के आयोजन में समारोह का आनंद लेने के बाद अवसरा आतोचानाएं करते ही पाए जाते हैं। इन मध्य शादी समारोहों में आयोजकों द्वारा सभी को दुनिया के सुखों को प्रदान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भौतिकवाद की चकाचौंध में विवाह-संस्कारों तथा रस्मों-रिवाजों की आत्मा ही धूटी है। सबसे बुरी हालत तो शादी संस्कारों को पूरा करवाने वाले कुल पुरोहित की ही है जिसे बुधांया मजदूर आधे घंटे में रस्मों-रिवाज पूरा करने के आदेश दे दिए जाते हैं। पुरोहितों को भी व्यवस्था से समझौता करना पड़ता है। वरमाला के समय वर पक्ष की ओर से दूल्हे के दोस्तों तथा वधु पक्ष की ओर से उसके भाइयों की फौज को वरमाला डालने या न डालने पर कई बार उलझते दे खा जाता है। आमोद-प्रमोद की क्षणों में विष्णु रूपी वर तथा लक्ष्मी विली वधु को अपने बैठद अंतरंग, अर्पण तथा महत्वपूर्ण क्षणों में भी तानाती का सामान करना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के अनुसार जयमाला के क्षण वर एवं वधु के लिए बहुत ही अंतरंग एवं महत्वपूर्ण होते हैं तथा इसमें किसी भी अनावश्यक नाटक का अन्य पात्रों की आवश्यकता नहीं होती। समाला बहुत ही सरल तथा सहज ढंग से प्रणय की जानी वाहिए। इसी प्रकार लग्न, सात फेरों, हवन, वेदिका, मांग भराई आदि संस्कारों का विदि-विधान से पालन होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में परिवार के कुल पुरोहित को गुरु माना जाता है। उनके निर्देशनुसार विधानपूर्वक संस्कार संपन्न होना चाहिए। विवाह संस्कार में द्वारा रोकना तथा जूते चुराना इत्यादि रस्में भी वर-वधु एवं उनके भाइयों-बहनों, दोस्तों, सहेलियों के बीच हंसी-स्तुशी, आमोद-प्रमोद का एक कारण है, लेकिन इसके नाम पर भी भारी भरकम राशि मांगने की शर्त पर अडे रहने से भी कई बार आंखें मैली होती हुई दिखाई देती हैं। किसी भी शादी समारोह के आयोजनों में बहुत से लोगों के हित, आजीविका तथा भावनाएं जुड़ी होती हैं जिन्हें पूरा किया जाना आसान कार्य भी नहीं होता। भौतिकवाद की चकाचौंध में पूरी तरह से आनंद लें,

केन शादी से पूर्व कुछ बातें—वधु, तथा उनके अधिभावक विदारी से सुनिश्चित कर लें कि वही भी प्रकार का अन्न-घन तथा धन्यवाद का अपवाह न हो। ठिंडू कृति से शादी संस्कार संपन्न हो जाएगी तो रीति-रिवाजों का उपहास उड़ने दें। वरमाला, लग्न, वेदी, न, सात फेरों, मांग भराई, शादी शर्तों की गरिमा एवं गमीरता का न रखे। शादियों में भारी—भरकम नफूदु संगीत से शरीर झूम सकते लेकिन आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। भारी आवाजों के करण और विचारों का आदान-प्रदान नहीं हो पाता। अपनी सस्कृति रीति-रिवाजों को अधिगमन हें भोजन की बराबादी किए बिना पूज्ये पेट क्षयिकों की भूमध्य शांत हो सकती है। अपनी बुद्धि और विचारों से बहुत ही संवेदनशील नियन्त्रण लेकर साधारण एवं विवाह समाप्तों का गरिमामय आयोजन करें फिजूलखर्वी को रोक कर अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। विवाह संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण और विशरणार्थी संस्कार होता होता है। इसके रीति-रिवाजों, संस्कारों का भद्रा मजाक नहीं बनना चाहिए

शादी की रस्मों का बनता भद्रा मजाक

**दूसरे प्रदर्शनालयात युग्मापा न इता बार त्राकृष्णा
बनेंगे भाजपा के चुनावी सारथी!**

के नाम पर कई युगाव लड़ और जीत के देख लिये, लेकिन अब जबकि अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है और अब वहां सियासत चमकाने का कोई मौका नहीं बचा है तो बीजेपी ने अपना फोकस अयोध्या से हटाकर प्रभु श्रीकृष्ण का सियासी पारा सातवें आसामन पर पहुंच गया। केशव प्रसाद मौर्या ने अपने इस टीवीट को अपने टिवटर प्रोफाइल पर पिन भी कर दिया है। उप-मुख्यमंत्री के ऐसे टीवीट के कई निहिताथ निकाले जा रहे हैं। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी थी जो अवानक उसको भगवान

कानूनी तौर पर इस संस्था को जीमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था लेकिन इसने द्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएँ निमानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जीमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दाखिल किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता

उम्मीद लाए बैठे हैं कि बीजेपी की सरकार यहां भी श्रीकृष्ण भक्तों को इंसाफ दिलाएगी। उत्तर प्रदेश हो, उत्तर भारत हो या यूं कहें कि पूरा देशकृष्णभगवान श्रीकृष्ण हर जगह किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। श्रीरामजन्मभूमि के साथ लोगों

देन परिश्रम से परीक्षा देने पर हृचरते जहां उन्हें पता चलता है कि वे और लीक होने से परीक्षा रद्द हो। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा लीक प्रकरण ने व्यवस्था को सिरे से सोचने पर मजबूत किया थी। यांकी की मौजूदा हुक्मसंत को वर्ती सरकारों के मुकाबले से बचाया गया। परार्डी माना जाता है। बापज़द की अंतिम रात तक प्रश्नों पत्रों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारियों व सुरक्षाबलों के अधीन होती है। ये जिम्मेदारी चंद विश्वसनीय लोगों के कंधों पर होती है जिसमें कौन-कौन सामिल होते हैं उनकी जानकारीय मंत्री एवं लेकर मध्यमीय तक को भी दी जाती है।

की जन्मस्थली मधुरा में कन्द्रित कर लिया है। बीजेपी 2022 के बिंदु गानसभा कुनाव में रामलला की इतिहास पर ही प्रभु श्रीकृष्ण को अपना नया सारथि बनाने जा रही है। इसका वैसे किसी को कोई खास आभास नहीं था ले कि न उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मधुरा वाले बयान ने बीजेपी की भविष्य की राजनीति का जैसे खाका ही खींच कर रख दिया है। इस बयान के बाद मधुरा पर सियासत तेज हो गई है जिसमें उपमुख्यमंत्री ने कहा था, 'अब मधुरा की तैयारी है।' मौर्या के इस बयान से विपक्ष बौखला गया है तो बीजेपी मौर्या के बयान के 'ताप' के नापने में लगी है। यदि बीजेपी की अपनी हिन्दूत्व वाली सियायत में मौर्या का बयान फिट बैठ गया तो अगले वर्ष होने वाले यूपी विधानसभा कुनाव ही नहीं आगे के भी कई लोकसभा और राज्यों के बिंदु नांसभा चुनावों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अयोध्या की तरह गरमता रहेगा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा कुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विस्तार विभाजन शुरू कर दिया है। चुनाव में अयोध्या में मंदिर निर्माण, अव्याजान, जिना, कलाम, पलायन, मुरिलम टुटिकरण, साम्प्रदायिकता, किसान, गन्ना सबके नाम पर राजनीति हो रही है, तो भारत भगवान भी इस कुनाव में उत्तर बिना कैसे बच सकते थे। हर बार राम जन्मभूमि मंदिर को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी ने अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, तो इस पर किसी को कोई आश्वर्य नहीं है। बीजेपी अलाकमान ने कभी काशी और मधुरा पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया हो, लेकिन अक्षर बीजेपी के नेता और हिन्दूवादी संगठन सार्वजनिक मंचों से 'अभी मधुरा-काशी बाकी है' का नारा श्रीकृष्ण का अपना सारथी बनाने की जरूरत पड़ गई। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सालों से चलता आ रहा है। मगर अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनाने की बीजेपी की मुहिम के चलते ही बीजेपी के अंदरखाने श्रीकृष्ण की जन्मस्थली का लेकर कहीं कोई ज्यादा सक्रियता नहीं देखी गई। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मधुरा के तीन याचिकाताओं—रंजना अर्णिहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और तीन अन्य ने मधुरा की जिला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया था कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढाँचे का निर्माण कर दिया। भगवान श्रीविष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का जन्मस्थान उसी ढाँचे के नीचे स्थित है। इसको लेकर मधुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया और 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगने के साथ ही शाही ईदगाह मरिजिद को हटाने की मांग की गई थी। बताते चले कि मधुरा में शाही ईदगाह मरिजिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ठीक वैसे ही लगी हुई बनी है जिसे मुगल मैं लकड़ी में काशी में बाबा भोलेनाथ के मंदिर के बगल में ज्ञानपीठ मरिजिद का निर्माण कराया गया था। अयोध्या में रामलला का मंदिर ध्वस्त करके कथित तौर पर बाबरी मरिजिद बनवाई गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि औरेंगजेब ने प्राचीन कंशवनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और शाही ईदगाह मरिजिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाराणसी के दिवू राजा जो जमीन के कानूनी अधिकार साँपंदिए थे जिस पर मरिजिद खाड़ी थी। 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा

कर लिया। 1968 के समझौते के अनुसार, शाही ईदगाह कमिटी और श्री कृष्णगूप्त द्रस्ट के बीच एक द्रस्ट के पास रही और मरिजिन को प्रबंधन अधिकार मुस्लिम कमिटी को दिए जाएंगे। अब प्रभु श्रीकृष्ण के भक्तों द्वारा इसी समझौते को कोर्ट में तुनौती दी जा रही है। इसमें भी बीजेपी के पास चुनाव में भुनाकर श्रीकृष्ण जनन्मभूमि को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। श्रीकृष्ण जनन्मभूमि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, इसके सकंत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अपने एक भाषण के दौरान दे चुके हैं। अयोध्या में दीपतिवस के पांच पर सीएम योगी के कहां था, '1990 में राम मंदिर बोलना अपराध माना जाता था, यह लोकतंत्र की ताकत है कि जो 31 साल पहले रामभक्तों पर गोलियां चलाते थे आज आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर आप कुछ वर्ष और इसी तरह से ले चलते थे अगली कारसेवा के लिए वे और उनका पूरा खानदान लाइन में खड़े होते दिखाया देंगे। आप देखना अगली कारसेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब रामभक्तों-कृष्णभक्तों पर पुष्टों की वर्षा होगी। यही लोकतंत्र की ताकत है। गत दिनों दिल्ली सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो टीवी किया है, उसमें उड़न्होंने एक तरह से सीएम योगी के भाषण को ही आगे बढ़ाया है। श्रीकृष्ण जनन्मभूमि के ऐतिहासिक पक्ष को समाजने की कोशिश की जाए तो 1679 में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए थे। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिन्दुओं की आस्था पर चोट करना इसका मूल सदृश्य। इसके अलावा इसके आर्थिक उद्देश्य थी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफी धन संपदा होती थी जिसे औरंगजेब ने लूट लिया था। श्रीकृष्ण जनन्मभूमि मंदिर को भी उररी समय तोड़ा गया था।

पारस्या नामा जाता है, बायोपूर्वक विश्वास की कृत्य वैसे ही हो रही है। अधिकार्यमंत्री योगी आदिल्यनाथ ने खल हज़ेर में आरोपियों को चिह्नित कराई वाले एवं वितरित कराई वाले और दोषियों की संपत्तियों की जबकी की बात दी है। दरअसल, ऐसा करना भी ही हो गया है, जब तक कोई सिङ्किट को तिरत-वितरित किया जाता, भर्ती परीक्षाओं लीक प्रफ करने की परिकल्पना कार नहीं हो पाएगी।

उत्तराखण्ड वै ये पहला मामला नहीं है और इसमें भी नहीं है। शासन-प्रशासन पाप लीलौक पर लगाव का इस अधिकार भारतीय तरीका भी नहीं। घटनाओं के बाद ताबड़तोड़ विपरीतारियां होना, आरोपियों को जामनात भिन जाना, ये तरीका बीमारी का विकल्प नहीं हो सकते। कुछ और सुकम्पल तरीका जाना होगा। प्रशनपत्रों को लीक वाना जालसाजों का पुराना और नदानी धंधा है। टीईटी परीक्षा के प्रकरण में अभी तक जितनी विपरीतारियां हुई हैं, वह मोहरे वाले हैं, बड़ी मछलियां अब भी जाल नहीं फर्जी हैं। उन तक पहुंचने वाली दरअसल, इस विवरणधंधे में सफेदपोशों से लेकर लिंगपत्र के सिस्टम के भेड़िए भी जुड़े हैं। जाहिर है बिना उनके अधिकारीयों से इतना बड़ा कांड करना नहीं, सरकारी तंत्र के अधिकारों एक बड़ा सिङ्किट पनाया है जिसे भेदना जरूरी है। वितरित कराना वालों द्वारा दिसंबर को दोबारा परीक्षा जाएगी, जिसके लिए उनसे कोई वितरित क्षुल्क व बर्तों का किराया लिया जाएगा। पर, क्या ऐसा

लकर तुक्राना तो क्या ना देखा जाती है। इस दरवाजान कोने बहुत आसान होता है। बहरहाल, इस तंत्र में बड़ी गिलियगत होती है। प्रश्नपत्र लीक प्रकरण सफलता से कई लोग रातों-साता मालामाल हो जाते हैं। पेपर लीकों कांड देश के विभिन्न हिस्सों पर समय-समय पर होते रहते हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश में ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है।

बदमाशों का ये खेल कितनी परीक्षाओं में सफल हुआ, जिसका हम अप अंदराजा भी नहीं लगाना सकते। इनका तंत्र बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जालसाज टीईटी परीक्षा में गच्छा खा गए। इससे पहले भी एकाथ परीक्षाओं में ये सब-इंप्रेक्टर पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल प्रश्नपत्र लीक हुआ, इसी वर्ष पुलिस भर्ती पेपर भी येप पार्ट भुआ। कटी लंबी है। 2018 में ही अधीनरथ सेवा पेपर, स्वास्थ्य विभाग प्रोनेश्ट पेपर, नलकपु आपरेटर पेपर, 41520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ पिछले साल 69000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक हुआ और अब यूपीटी लीक हो गई। ये सिलसिला कब रुकेगा, किसी नहीं पता? पर, इससे अभियाकरों और परीक्षार्थियों का मनोबल जरूर ढूटा जा रहा है। इससे अच्छा तो पूर्व की असंविधानिक व्यवस्था ही ठीक थी, जब धूस देकर आदामी नौकरी पा लेता था हालांकांत व्यवस्थाओं का लोकतंत्र मान्यता नहीं देता वाला देनी भी नहीं चाहिए। कुल गिलाका लीकेज के ये आकड़े सामान्य नहीं हैं, इन्हें करत इन जर्जर दाज नहीं किया जाना चाहिए। सिंप यूपी सरकार को ही क्रेंडर सरकार से लेकर समूचे भारत के जर्जरों द्वारा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे प्रतियोगी परीक्षा लीकेज प्रफ हो सके। सतर्कता नहीं बरती गई तो ये सके।

